भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 247

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाला राज्य

247. श्री दामोदर अग्रवाल:

- श्री दिलीप शङ्कीया:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री महेश कश्यप:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का ब्यौरा क्या है;
- (ख) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत छप्पन अतिरिक्त वाटरशेड विकास परियोजनाओं (डब्ल्यूडीसी) के लिए दस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहचान करने के लिए निर्धारित विशिष्ट मानदंड क्या हैं;
- (ग) क्या उन राज्यों में राजस्थान सभी मानदंडों को पूरा करता है, यदि हां, तो राजस्थान के पाली जिले के लिएस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या क्या है, यदि हां, तो वहां उपलब्ध मौजूदा वाटरशेड परियोजनाओं के प्रभाव सहित इसका ब्यौरा क्या है;
- (घ) परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के अन्य भागों में भी इसी तरह के मॉडल को लागू करने या दोहराने की योजना बना रही है;

(च) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) ये परियोजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, भूमि क्षरण की समस्या का समाधान करने और जलवायु लचीलापन से संबंधित प्रयासों को मजबूत करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होंगी?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 49.5 लाख हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य और केंद्रीय हिस्से के रूप में 8,134 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, विभाग ने अब तक, 28 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिए 12,303.33 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 8022.69 करोड़ रुपये) की कुल लागत पर 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 1150 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत से, राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 4616.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। (दिनांक 28.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार)

(ख) और (ग) अतिरिक्त परियोजनाओं की मंजूरी के लिए राज्यों का चयन पहले से ही स्वीकृत डब्ल्यूडीसी-2.0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनके प्रदर्शन के आधार, जैसे कुल परियोजना लागत के एवज में किए गए व्यय का प्रतिशत; प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) घटक पर किए गए व्यय का अनुपात; अवक्रमित भूमि/बंजर भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत; पहाड़ी राज्यों में स्प्रिंगशेड कार्यकलापों की संभावना, पर किया गया था। अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए राज्य-वार अनंतिम क्षेत्र का आबंटन अनुबंध-1 में दिया गया है।

राज्यों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर परियोजना क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा और फिर विभाग द्वारा इनका मूल्यांकन और मंजूरी दी जाएगी।

पूरी की गई वाटरशेड परियोजनाओं की एंड लाइन रिपोर्टों से पता चलता है कि परियोजना क्षेत्रों में सतही और भूजल की उपलब्धता, उत्पादकता में वृद्धि, वानस्पतिक आवरण, आजीविका के अवसरों में वृद्धि और घरेलू आय में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

(घ)कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में वाटरशेड विकास निधि के सृजन का प्रावधान है जिसका उपयोग वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवों के चयन हेतु अनिवार्य शर्तों में से एक, वाटरशेड विकास निधि में लोगों का अंशदान है। इस निधि का उपयोग प्राथमिक हितधारकों के लाभ के लिए सृजित सामान्य परिसंपत्तियों की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन के लिए किया जाना चाहिए, जिसे मनरेगा आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

(ड) और (च)डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, भूमि संसाधन विभाग ने मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों सहित 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के लिए 8214 परियोजनाओं (वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक) को मंजूरी दी थी। इसी तरह, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, भूमि संसाधन विभाग ने अब तक मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों सहित 28 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) को 1150 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(छ)डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई, कई उपायों के माध्यम से, भूमि अवक्रमण की समस्याओं को दूर करने और उत्पादकता में सुधार करने का प्रयास करता है। वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, सतही और भूजल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार होता है, उत्पादकता में वृद्धि, वनस्पति आवरण तथा आजीविका के अवसरों में वृद्धि और परियोजना क्षेत्रों में घरेलू आय में वृद्धि होती है।

बढ़ी हुई कृषि आय और पोषण सुरक्षा के अलावा, वाटरशेड प्रबंधन, वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों में कई सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव जैसे ऑक्सीजन का रीसाइक्लिंग, कार्बन पृथक्करण आदि का सृजन करता है। यह पूरे परिदृश्य का पुनरुद्धार करता है जिससे अवक्रमित मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है और भूजल का संपोषण होता है, सतह अपवाह में तथा मृदा के कटाव और जलाशयों के अवसादन में कमी होती है। स्प्रिंग्स पुनरुद्धार, बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए किसानों के बेहतर अनुकूलता के माध्यम से निरंतर विकास सुनिश्चित करता है और वाटरशेड समुदायों के लिए आजीविका के अवसर का सृजन करता है।

दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 247 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र का अनंतिम आवंटन

क्र. सं	राज्य	अतिरिक्त आवंटित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिरिक्त परियोजनाओं की अनंतिम संख्या
1	राजस्थान	54305	11
2	मध्य प्रदेश	39632	8
3	कर्नाटक	39413	8
4	ओडिशा	33003	7
5	तमिलनाडु	27171	5
6	असम	27621	5
7	नागालैंड	20186	4
8	हिमाचल प्रदेश	14425	3
9	उत्तराखंड	14244	3
10	सिक्किम	10000	3
	कुल	280000	57

प्रत्येक राज्य में एक परियोजना के लिए क्षेत्र लगभग 5000 हेक्टेयर अनुमानित किया गया है और इसके आधार पर परियोजनाओं की संख्या का अनुमान लगाया गया है। संभवतः, पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजनाओं का इकाई क्षेत्र कम होकर प्रति परियोजना 3000-4000 हेक्टेयर के बीच होगा। अतः तालिका में अनुमानित परियोजनाओं की संख्या, राज्य में सुविधा और क्षेत्र उपलब्धता के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी।

दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 247 के भाग (ड) तथा (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 और 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति का विवरण

क्र. सं	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	
		डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई -1.0	डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई -2.0
1	आंध्र प्रदेश	432	59
2	अरुणाचलप्रदेश	156	68
3	असम	372	31
4	बिहार	123	35
5	छत्तीसगढ़	263	45
6	गोवा	--	5
7	गुजरात	610	51
8	हरियाणा	88	9
9	हिमाचल प्रदेश	163	26
10	झारखंड	171	30
11	कर्नाटक	571	63
12	केरल	83	6
13	मध्य प्रदेश	517	85
14	महाराष्ट्र	1186	140
15	मणिपुर	102	13
16	मेघालय	96	32
17	मिजोरम	89	20
18	नागालैंड	111	10
19	ओडिशा	310	53
20	पंजाब	67	7
21	राजस्थान	1025	149
22	सिक्किम	15	6
23	तमिलनाडु	270	28

24	तेलंगाना	330	35
25	त्रिपुरा	65	19
26	उत्तराखंड	65	12
27	उत्तर प्रदेश	612	56
28	पश्चिम बंगाल	163	27
29	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	144	19
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	15	11
	कुल	8214	1150

मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र में सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिले आते हैं। स्वीकृत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं का वितरण निम्नानुसार है:

जिला	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	
	डब्ल्यूडीसी-1.0	डब्ल्यूडीसी-2.0
सीधी	7	2
सिंगरौली	8	0
शहडोल	6	0